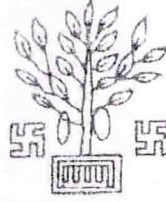


नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
अध्यक्ष

राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
बिहार

पत्रांक / Ref. No. : 639/14

दिनांक / Date : 21/8/14

माननीय मंत्री,
सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
तथा विधि विभाग,
बिहार, पटना ।

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुर के अनुमण्डल मुख्यालय झंझारपुर में **अपर जिला एवं सत्र न्यायालय** की स्थापना का विषय काफी दिनों से प्रक्रियाधीन है । जिला मुख्यालय से काफी दूर होने के फलस्वरूप झंझारपुर अनुमण्डल के नागरिकों को आये दिन न्यायिक कार्यों से जिला मुख्यालय मधुबनी जाने में होती परेशानियों को देखते हुए झंझारपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग पूर्व से की जा रही थी ।

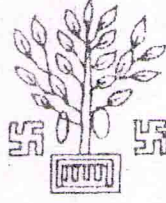
निबंधक(प्रशासन) एवं महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमंडल मधुबनी के अन्तर्गत झंझारपुर में स्थायी रूप से **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश** के पदों के सृजन का प्रस्ताव अगस्त एवं दिसम्बर 2013 में राज्य सरकार को समर्पित किया गया था ।

इस संबंध में विधि विभाग द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद झंझारपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद में आया । तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री **श्री नीतीश कुमार जी** की अध्यक्षता में 15 मई, 2014 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी ।

इन पदों के सृजन के उपरान्त झंझारपुर अनुमण्डल के नागरिकों को झंझारपुर में ही न्यायिक प्रक्रियाओं के निष्पादन की उम्मीदें पूरी होती दिखने लगी ।

इस बीच अपर जिला एवं सत्र न्यायालय झंझारपुर के परिचालन के उद्देश्य से निबंधक(प्रशासन) उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-9022 दिनांक-21.12.2013 के आलोक में, झंझारपुर अनुमण्डल में अपर जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के क्रम में 22 जुलाई, 2014 में माननीय मुख्यमंत्री **श्री जीतन राम मांझी जी** की अध्यक्षता में

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
अध्यक्ष

राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
बिहार

पत्रांक / Ref. No. :

दिनांक / Date :

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय संवर्गों के 14 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई । इनमें सिरस्तेदार, लिपिक, स्टोनोग्राफर, डिपोजीशन राईटर, चालक एवं पिउन/अर्दली के पद शामिल हैं ।

इस संबंध में आपका ध्यानाकृष्ट कराना है कि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों सहित विभिन्न आवश्यक संवर्गों का पद सृजन किए जाने के बावजूद अभी तक झंझारपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का परिचालन व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सका है । झंझारपुर सहित निकटस्थ क्षेत्रों के निवासियों के प्रतीक्षा की घड़ी लम्बी होती जा रही है ।

अतएव, आग्रह है कि, झंझारपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का सुव्यवस्थित परिचालन आरम्भ कराने हेतु आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे ।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitish Mishra
21.8.11
(नीतीश मिश्रा)